

प्रतापगढ़ संदेश

गोशाला को स्वावलम्बी बनाने का हो प्रयास : मण्डलायुक्त

मण्डलायुक्त ने बराछा स्थित गोशाला का किया निरीक्षण

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। प्रयागराज मण्डलायुक्त संजय गोयल ने सोमवार को प्रतापगढ़ पहुंचकर जिलाधिकारी डा० नितिन बंसल के साथ नार पालिका की गोशाला का निरीक्षण, स्कूल चलो आधिकारी नार पालिका की गोशाला का निरीक्षण किया।

अयुक्त का सोमवार को अप्राह्ण एक बजे बराछा स्थित गोशाला पहुंचा। उनके साथ जिलाधिकारी डा० नितिन बंसल, सीटीओ ईशा पिंडा, एसटीएम सीम्प मिश्रा, नार पालिका के अधिकारी अधिकारी मुदित सिंह के अलावा गोशाला प्रश्नभरण अधिकारी के लावा



बराछा स्थित गोशाला का निरीक्षण करते मण्डलायुक्त व डीएम।

अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। संसाधनों से ही अपना व्यवहार आधे घंटे के निरीक्षण में निकालना होगा। इस बारे में गोबर आयुक्त संजय गोयल ने गोशाला को स्वावलम्बी बनाने के भी सुझाव पर चर्चा की गई। बहाने मौजूद जिलाधिकारी डा० नितिन बंसल ने कहा कि इन दिनों हीरे चारों की

समस्या है। ऐसे में नार पालिका मूली माडी से बच्चे हरी सब्जियों की खिलाया जाए। गर्भी में पशुओं के पैंपों के पानी व स्वाने पर विशेष सतकता बरतने पर भी जोर दिया जाए। इस बारे में नार पालिका के सफाई निरीक्षण संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मण्डलायुक्त गोशाला की साफ-सफाई से संतुष्ट नजर आए। आयुक्त संजय गोयल ने रायगढ़ में स्कूल चलो अधिकारी व प्रश्नभरण के अधिकारी मौजूद लिया तथा शाम को मैडिकल कालेज के मौजूदों का हाल-चाल लेने पहुंचे। जिले के सारे अधिकारी आज मण्डलायुक्त के अगमन को लेकर सतर्क एवं चैकस दिखाई दिये।

दबंगों ने होमगार्ड को रास्ते में दौड़ाकर पीटा

परियावां, प्रतापगढ़। रविवार की शाम को तोतवाली इयूटी पर जा रहे होमगार्ड राम चन्द्र यादव को आधा दबंग की संख्या में दबंगों ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। पहले से लाटी डंडा से रास्ते में घात लगाए बैठे दबंगों ने इयूटी पर जा रहे होमगार्ड रामचन्द्र यादव को दबंगों ने खेत में जानवर जाने के विवाद में होमगार्ड को जमकर मारा पीटा। सरे आम हो रही होमगार्ड की पिटाई से क्षेत्र में हड्कम्प मच गया। नारी को बोलने की हिमत नहीं पड़ रही। पीटित होमगार्ड के परिजनों ने चार लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को घटना की नामजद तहरीर दिया है। पुलिस ने मारने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।



स्कूल चलो रैली में शामिल शिक्षक व बच्चे।

मॉडल प्रा० वि० जहनईपर में निकली स्कूल चलो रैली

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। सदर विकास खंड के मॉडल प्राथमिक विद्यालय जहनईपर में आज मुख्यमंत्री के स्कूल चलो अभियान के लाइव प्रसारण के बावजूद विद्यालय में बच्चों अधिकारिकों एवं शिक्षिकों ने स्कूल चलो रैली निकली। पूरे गांव का भ्रमण करने के उत्तराव विद्यालय में शिक्षिकों की गई। सांगीती को संबोधित करते हुए प्रधानाध्याधिकारी प्राची पांडे ने कहा कि सभी का शिक्षित होना जरूरी है। सभी लोग सरकारी विद्यालयों में बच्चों का दाखिला करा कर कर निःशुल्क अपने बच्चों को केवल शिक्षित बनाये बत्ति उत्तम शिक्षण व्यवस्था का लाभ प्राप्त करें। सांगीती को शिक्षक विजयराज यादव, अरुण मिश्र, पुष्णा पटेल, कृष्ण यादव, रितु, सजला, राणी, अशोक वर्मा, सराजा, जय देवी आदि उपस्थित रहे।

हाईस्कूल विज्ञान में 7056 कलेक्ट्रेट और तहसीलों में तटकते रहे ताले परीक्षार्थी अनुपस्थित

परीक्षा केन्द्रों पर रही परीक्षार्थियों की भीड़

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। माध्यमिक शिक्षा परिषद 70०४० की चतुर रही परीक्षाओं में आज सोमवार को प्रथम बेटा में हाईस्कूल विज्ञान की परीक्षा में कुल 57122 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 7056 परीक्षार्थी अनुपस्थित हो गये। केवल 50116 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इसमें 2697 छात्रों व 23 छात्राएं शामिल थी।



अधिकारी परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करते रहे। इनके अलावा परीक्षा केन्द्रों का अंतरिक परीक्षा दल भी परीक्षार्थियों की तलाशी लेता

एसडीएम की गिरफ्तारी न होने से कर्मचारियों में रोष



एसडीएम की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करते कर्मचारी।

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। नायब नाजिर की पिटाई से हुई मौत के मामले में अपरोपी एसडीएम जानेन्द्र विक्रम सिंह की गिरफ्तारी न होने से कर्मचारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट व तहसील में पूर्ण हड्डियाल रखी। इस बारे में इंटर वीजी जीवन और गणित की परीक्षा थी जिसमें कुल 30316 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 3060 अनुपस्थित हो गये। बीचे 27256 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इनमें छात्रों की संख्या 17100 और छात्राओं की संख्या 10156 रही।

कामकाज ठप रहा।

प्रतापगढ़। नायब नाजिर की पिटाई से हुई मौत के मामले में अपरोपी एसडीएम जानेन्द्र विक्रम सिंह की गिरफ्तारी न होने से कर्मचारियों ने सोमवार को कलेक्टर व तहसील में पूर्ण हड्डियाल रखी। इसके बाद विक्रम सिंह ने दिलाई में एसडीएम की मौजूदगी में उसके इलाज में लापरवाही की गई जिससे शिनिवार को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद प्रशासन ने एसडीएम के विरुद्ध हत्या का मुकदमा लालंग में दर्ज करा दिया। इसके

नायब नाजिर की हत्या से वकीलों तथा कर्मचारियों में उबाल

अखंड भारत संदेश

लालंग, प्रतापगढ़। हड्डील में जीवन नायब नाजिर हत्या के लोकर सोमवार को अधिकारी व तहसील के अधिकारियों तथा बाल देखा गया।

हालांकि शासन ने हत्या का विरोध नायब नाजिर के बावजूद देखा गया। नायब कर्मचारियों ने तहसील में लालंग में एसडीएम की मौजूदगी में उसके इलाज में लापरवाही की गई जिससे शिनिवार को उसकी मौत हो गई। यह नायब के बाल देखा गया। नायब कर्मचारियों ने तहसील के उपरांत में एसडीएम की मौजूदगी में उसके इलाज में लापरवाही की गई जिससे शिनिवार को उसकी मौत हो गई। नायब कर्मचारियों की मार्ग है कि प्रधान अधिकारी नायब नाजिर के बाल देखा गया।

बाद से एसडीएम फरार चल रहे हैं।

उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है।

है कि एसडीएम को गिरफ्तार किया जाए और मूर्क के परिजनों को गिरफ्तारी के बावजूद सिंह को गिरफ्तार किया जाए। जब तक ये मार्ग पूरी नहीं हो जाए। जबकि अधिकारी व नायब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए तो वकील देखा गया।

वकील देखा गया है।

इसके बाद विक्रम सिंह ने दिलाई में एसडीएम की गिरफ्तारी के विरुद्ध सिंह को लिलिमित कर दिया है। विरोध से निलिमित जमकर नायब नाजिर की मार्ग है।

आरोपी एसडीएम जानेन्द्र विक्रम सिंह की गिरफ्तारी हो रही है।

एसडीएम को गिरफ्तार किया जाए और मूर्क के परिजनों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक ये मार्ग पूरी नहीं हो जाए। जबकि अधिकारी व नायब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए तो वकील देखा गया।

है कि एसडीएम को गिरफ्तार किया जाए और मूर्क के परिजनों को गिरफ्तार किया जाए। जबकि अधिकारी व नायब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए तो वकील देखा गया।

है कि एसडीएम को गिरफ्तार किया जाए और मूर्क के परिजनों को गिरफ्तार किया जाए। जबकि अधिकारी व नायब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए तो वकील देखा गया।

है कि एसडीएम को गिरफ्तार किया जाए और मूर्क के परिजनों को गिरफ्तार किया जाए। जबकि अधिकारी व नायब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए तो वकील देखा गया।

है कि एसडीएम को गिरफ्तार किया जाए और मूर्क के परिजनों को गिरफ्तार किया जाए। जबकि अधिकारी व नायब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए तो वकील देखा गया।

है कि एसडीएम को गिरफ्तार किया जाए और मूर्क के परिजनों को गिरफ्तार किया जाए। जबकि अधिकारी व नायब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए तो वकील देखा गया।

है कि एसडीएम को गिरफ्तार किया जाए और मूर्क के परिजनों को गिरफ्तार किया जाए। जबकि अधिकारी व नायब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए तो वकील देखा गया।

है कि एसडीएम को गिरफ्तार किया जाए



संपादकीय

महाराष्ट्र कांग्रेस की लड़ाई^१ उभरकर सामने आई

महाराष्ट्र कांग्रेस के आपस के झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डर यही है कि कही पंजाब की तरह यहाँ भी नेताओं के आपसी अहं का टकराव और लड़ाई इतनी नहीं बढ़ जाये कि राज्य में भी कांग्रेस पूरी तरह खदान हो जाये। पहले ही कांग्रेस राज्य में चौथे नंबर की पार्टी बन गयी है औ? उसके पास केवल 42 बायालीस ही विधानसभा के सदस्य बचे हैं। उनमें से भी कई बीजेपी जाने को बेकरार हैं बस सत्ता के कारण टिके हुये हैं। हमें मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक सर्वे कराया है जिसमें बताया गया है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो सबकं कमजोर कड़ी कांग्रेस ही साक्षित होगी और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 28 तक हो सकती है इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है पहली तो ये कि वो एक तरफ एनसीपी और शिवसेना के नेताओं और मंत्रियों पर हमले करके उनको संभलने का मौका नहीं देगी दूसरी तरफ वो कांग्रेस के विधायकों को पहले तोड़ने और फिर उनको चुनाव में हराने की कोशिश करेगी। असल में बीजेपी को उम्मीद है कि वो कांग्रेस को सीधी टक्कर में हरा सकती है क्योंकि कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझे हुये हैं। यही रणनीति वो बीएमसी के चुनाव में भी करने वाली है। बीएमसी में भी अभी कांग्रेस के 28 नगर सेवक ही जिनकी सीटों पर बीजेपी सीधे जीतकर अपनी संख्या इतनी बढ़ाना चाहती है कि बीएमसी पर उसका कब्जा हो जाये इसलिए उसने कांग्रेस के कृपाशंकर सिंह से लेकर राजहंस सिंह तक सभी उत्तर भारतीयों को तोड़ लिया है। महाराष्ट्र में असल में बीजेपी को लगता है कि अगर अभी चुनाव हुये तो शिवसेना कम से कम 55 और एनसीपी 53 सीट जीत सकती है जबकि कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जो सबसे कमजोर है। असल में कांग्रेस के पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सदस्य विदर्भ से ही चुनकर आये थे और वहाँ पर उसकी सीधी टक्कर बीजेपी से ही है। इस बार मजेदार बात ये है कि बीजेपी के देवन्द्र फणनवीस और कांग्रेस के नाना पटोले दोनों ही विदर्भ के हैं और दोनों पहले एक ही पार्टी में काम कर चुके हैं। नाना पटोले भी सिद्धू की तरह ही कई पार्टीयों में और आखिर में बीजेपी में थे और बाद में कांग्रेस में आकर पार्टी अध्यक्ष तक पहुंचे। उनकी स्टाइल भी सिद्धू की तरह है जहाँ वो खुद ही अपने गठबंधन की सरकार और कांग्रेस के ही मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाते रहते हैं। नाना की तो विदर्भ से मंत्री विजय वडेटीवार, नितिन राऊत, सुनील केदार औ? यशोमती ठाकुर किसी से नहीं बनती। असल में नाना पटोले को जब विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया तो उनका कद बढ़ गया था औ? उनको मुख्यमंत्री या कांग्रेस के चेहरे के तौर पर माना जाने लगा लेकिन उसके बाद नाना ने पार्टी प्रेसीडेंट बनने के लिए सिद्धू की तरह ही इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन बाद नाना को समझ में आया कि पार्टी अध्यक्ष के साथ साथ ठसक के लिए मंत्री पद भी चाहिये अब नाना कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन आलाकमान और महाराष्ट्र कांग्रेस के उनके ही साथी मंत्री नहीं बनने दे रहे हैं। उधर बीजेपी ने राज्यपाल के सहारे विधानसभा का अध्यक्ष पद भी एक साल से खाली रखा है। ऐसे में नाना की हताशा बढ़ती जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेताओं से दुश्मनी मोल ले रखी है यही वजह है कि आलाकमान कुछ भी कहे महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई बड़ा आदोलन खड़ा ही नहीं हो पा रहा है यहाँ तक कि डिजिटल मैंबरिशप भी बुरी तरह नाकाम रही।

आशीष वशिष्ठ

केलकर समिति ने भी 2002 में कहा था कि देश में 95 फीसदी किसानों की इतनी कमाई नहीं होती कि वो टैक्स के दायरे में आएं। मतलब साफ है कि पांच फीसदी किसानों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। खेती से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगने से इसका फायदा उन बड़े किसानों के पहुंचता है जो संपन्न हैं या फिर उन बड़ी कंपनियों को जो इस सेक्टर में लगी हैं।

सरकार को नातियों में
विरोधाभास है। टैक्स से छूट
के दायरे में खेतिहर जमीन से
मिलने वाला किराया, फसल
बेचने से होने वाली कमाई,
नरसरी में उगाए जाने वाले
पौधे से होने वाली आय, कुछ
शर्तों के साथ फार्महाउस से
होने वाली कमाई इत्यादि
आती हैं।

पिछले कई दशकों से इस बात पर चर्चा होती रही है कि अमीर किसानों को भी

आयकर के दायरे में लाया जाए। लेकिन तमाम विचार-विमर्श और चिंतन-मंथन के बाद भी कोई सरकार धनी किसानों पर टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। भारतीय राजनीति में शुरू से ही किसानों की गरीबी का भरपूर फायदा उठाया गया है। देश के राजनीतिज्ञों ने किसानों और गरीबों को एक दूसरे का पर्यायवाची बनाकर पेश करने की कोशिश की। एक किसान गरीब ही होगा लोगों के बीच इस मानसिकता को जान-बूझकर बढ़ावा दिया गया। अमीर किसानों की आय पर टैक्स लगाने की बात हर सरकार में की गयी, लेकिन आज तक यह फैसला नहीं लिया गया क्योंकि सभी को अपना बोट बैंक खोने का डर है। जमीनी हकीकत यह है कि हरित क्रांति आने के 5 दशक होने को हैं, जिसके दौरान हमने किसानों की आय को कई गुना बढ़ाते देखा है। हालांकि, आज भी इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक कृषि से होने वाली आय पर भारत में टैक्स नहीं लगता। देश के गरीब किसानों का समझ में आता है, लेकिन यह बात समझ से परे है कि अमीर किसानों की आय पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता है। क्या अमीर किसान इस देश के नागरिक नहीं है? अमीर किसानों की आय पर कर तो छोड़िए, सरकार उल्ल्या इन्हें बाकी किसानों के साथ ही भारी-भरकम सम्बिंदी प्रदान करती है। अब समय आ गया है कि आय कर के नियमों में बदलाव करके अमीर किसानों की आय पर भी कर लगाने का प्रावधान जोड़ा जाये। अगर यह कहा जाए कि 130 करोड़ की आबादी वाला यह देश सिर्फ साढ़े चार करोड़ लोगों के टैक्स के पैसों से चलता है, तो हैरान न हों। इसमें भी डेढ़ कराड़ करदाता ऐसे हैं, जिनका योगदान नाम भर का है। यानी व्यावहारिक तौर पर देश की कुल आबादी के तीन प्रतिशत से भी कम लोग आयकर देते हैं। कृषि से होने वाली आय पर कर ना लगने से अमीर किसान तो अपना कर बचाते ही हैं, साथ ही इस प्रावधान की वजह से भारत के आयकर इकट्ठा करने की प्रणाली में एक बड़ा ब्लैक होल बन चुका है। हाल के किसान आंदोलन में हमने हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को नजदीक से देखा। महंगे कपड़े, स्पोर्ट्स शूज और बड़ी-बड़ी गाड़ियां, बड़े ट्रैक्टर सभी कुछ थे उनके पास। फिर भी उनमें से एक भी



किसान आयकर नहीं देता। कई ऐसे किसान मिल जाएंगे, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है और वे कर देने के बजाय सरकार से ही वसूली कर रहे हैं, चाहे वह एमएसपी में बढ़ोतरी हो या उर्वरकों की कीमतों में सब्सिडी या फिर कम दाम पर या मुफ्त में बिजली। छोटे व्यवसायी इस समय कोरोना महामारी के कारण मार खा बैठे हैं। लेकिन इसके पहले उन्होंने काफी कमाया। वर्ष 2017 में नीति आयोग के सदस्य बिबेक देवराय ने सुझाव दिया था कि, एक सीमा के बाद कृषि से होने वाली आय पर भी कर लगाया जाना चाहिए। बिबेक देवराय ने इशारा किया था कि कई राज्यों में पहले कृषि आय पर टैक्स लगाने का प्रावधान था। बिहार (1938), असम (1939), पश्चिम बंगाल (1944), ओडिशा (1948), उत्तर प्रदेश (1948), हैदराबाद (1950), ब्रावनकोर और कोचीन (1951) एवं मद्रास और ओल्ड मैसूर (1955) में कृषि आय पर कर का कानून था। कुछ राज्यों में अब भी यह मौजूद है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने भी देवराय की बातों से सहमति जताई थी। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्म कमीशन ने साल 2014 में ही कहा था कि दूसरे पेशे के लोग कृषि आय के नाम पर टैक्स छूट की रकम हर साल बढ़ा रहे हैं। यह वास्तव में टैक्स छूट पाने का एक बेहतरीन जरिया बन गया है। सीएजी की रिपोर्ट में भी इस बात पर चिंता जताई गयी है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्म कमीशन ने सुझाव

कर बड़ी कंपनियां बहुत बड़ी रकम पर टैक्स से छूट पा लेती हैं। 2014-15 में कावेरी सीइस ने कृषि से 186.63 करोड़ रुपए की आय दर्शाया था। वहाँ मॉसांटो जैसी अमरीकी कंपनी ने 94.4 करोड़ कृषि से आय दिखाया था।

दिया था कि जिन किसानों की कृषि आय 50 लाख रुपये से अधिक हो, उनसे इनकम टैक्स लिया जाना चाहिए। जिन किसानों के पास चार हेक्टेयर से अधिक जमीन है, देश में उनकी आबादी कुल किसानों का सिर्फ चार फीसदी है, लेकिन उनकी कुल कृषि आय किसानों की कुल आमदनी का 20 फीसदी है। ब्रिटिश राज के दौरान 1925 में भारतीय कराधान जांच समिति ने कहा था कि कृषि से होने वाली आय पर टैक्स छूट का कोई ऐतिहासिक या सैद्धांतिक कारण नहीं है। केवल प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से कृषि को टैक्स से दूर रखा गया है। आज की तारीख में भी ये दोनों बातें अमूमन सही हैं। देश की आजादी के बाद पहली बार साल 1972 में बनाई गई केन्न राज समिति ने भी कृषि पर टैक्स की सिफारिश नहीं की। यहां तक कि केलकर समिति ने भी 2002 में कहा था कि देश में 95 फीसदी किसानों की इतनी कमाई नहीं होती कि वो टैक्स के दायरे में आएं। मतलब साफ है कि पांच फीसदी किसानों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। खेती से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगने से इसका फायदा उन बड़े किसानों के पहुंचता है जो संपन्न हैं या फिर उन बड़ी कंपनियों को जो इस सेक्टर में लगी हैं। सरकार की नीतियों में विरोधाभास है। टैक्स से छूट के दायरे में खेतिहर जमीन से मिलने वाला किराया, फसल बेचने से होने वाली कमाई, नरसीरी में उगाए जाने वाले पौधे से होने वाली आय, कुछ शर्तों के साथ फर्मांहाउस से होने वाली कमाई इत्यादि आती हैं। लेकिन कृषि पर होने वाली आय को दिखा

तीन नये कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान नेता एमएसपी के गारंटी कानून पर आमादा हैं, तो देशहित में एक विनम्र सुझाव है कि जिन किसानों के पास 2-3 हेक्टेयर से अधिक खेती-योग्य जमीन है और सालाना आमदनी 10-15 लाख रुपए से अधिक है, तो वे किसान आम करदाता की तरह आयकर दें। वे आयकर रिटर्न भी दाखिल करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 86 फीसदी किसानों के पास औसतन 2 हेक्टेयर या उससे भी कम जमीन है। वे गरीब हैं, लेकिन जो बड़े जमीदार हैं, जिनके पेट्रोल पंप भी चलते हैं और जो चमचमाती कारों में सवार रहते हैं, उन्हें आयकर में छूट क्यों दी जाए? प्रश्न यह भी है कि जब सरकार ने आयकर-छूट की नीति बनाई थी, तब आर्थिक स्थितियां कुछ और होंगी, लेकिन अब तो आर्थिक उदारीकरण का दौर है। बड़े किसान आयकर क्यों न दें? उन्हें सबसिडी क्यों दी जाती रहे? यदि एमएसपी की गारंटी देनी है, तो सभी 265 फसलों पर दी जानी चाहिए। फिलहाल सरकार और उसका आयोग सिर्फ 23 फसलों पर ही एमएसपी की घोषणा करते हैं। दूध, मक्खन, मछली, अंडा आदि मुहैया कराने और पशुपालन, मछलीपालन, मुरीखाना चलाने वालों को भी एमएसपी क्यों न दिया जाए? देश के प्रतिष्ठित कृषि विशेषज्ञ स्वामीनाथन ने अपनी रपट में अनुशंसा की थी कि गेहूं और धान पर एमएसपी देना बंद करें। उसके बजाय विविध फसलों पर एमएसपी तय किया जाए। यहां तक एमएसपी का सवाल है, चरण सिंह, देवीलाल और महेंद्र सिंह इकते भी इसे कानूनी दर्जा नहीं दिला पाए। मौजूदा दौर में यह और भी पेचीदा है, क्योंकि सभी राज्य सरकारों की सहमति भी अनिवार्य है।
पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कुछ किसान बहुत अमीर हैं। कईयों के पास सौ-सौ एकड़ जमीन है और वे असल में करोड़पति हैं, लेकिन वाकी सभी राज्यों में हमें गरीब किसान देखने को मिलते हैं। गरीब किसानों के भले के लिए अमीर किसानों पर आयकर लगाया जाना ही चाहिए।

रातों-रात स्टारडम की चाहत वाले टिक नहीं पाते



अनुभव की गलियों से गुजरना होता है। इन्हीं खासियतों की वजह से मीका सिंह आज सिंगिंग के मामले में बॉलीवुड के किंग कहलाते हैं। वह एक जबरदस्त परफार्मर हैं। मीका सिंह का एक रीएलटी शो झं स्वयंवर, मीका दी वोटी अगले महीने से स्टार भारत टीवी चैनल पर शुरू होने जा रहा है, जिसमें मीका अपने लिए एक उपयुक्त जीवनसाथी का चुनाव करेंगे। वह एक म्यूजिकल शो होगा, जिसमें करीब 30 युवतियां हिस्सा लेंगी। शो के बारे में उन्होंने कहा, “मैं शादी के लिए खुद को तैयार करने के लिए सब कुछ कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है मैंने अपनी खुराक कम कर दी है। मैं जीवन के इस नए चैप्टर को लेकर रोमांचित हूं। मैं एक ऐसी जीवनसाथी की तलाश में हूं जो मुझे समझ सके, मेरे परिवार को खुश रख सके और सबको साथ लेकर चल सके। उन्होंने कहा कि

उनका परिवार बस यही चाहता है कि वह अब वैवाहिक जीवन में भी सेटल हो जाएँ। उन्हें और कोई उम्मीद नहीं है। "मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरे काम के नेतृत्व को समझ सके, क्योंकि मैं यात्रा बहुत करता हूँ, सिंगर ने कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को शुभकामनाएँ देते हुए मीका सिंह ने कहा कि नशा और अपराध बढ़ाने वाले गांवों पर रोक लगाने का सरकार का फैसला उचित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवंत मान के साथ कई शो किए हैं और मान एक नेकटिल इंसान हैं। जीते दो वर्षों में लॉकडाउन के समय, मीका ने अपने एनजीओ डिवाइन टच के माध्यम से प्रतिदिन एक हजार लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की। एनजीओ अनेक शहरों में भलाई के कार्य कर रहा है।

अभिव्यक्ति

پاکستان کی سرکار اور انکے چون ہوئے حکمران

सजाव ठाकुर
तंत्रिता के बाद से

1947 में स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान के सरकार और उनके चुने हुए हूकम्रान लड़खड़ाते हुए शासन तंत्र चलाते रहे थे। यहाँ हाल इमरान खान का हो चुका है। इमरान खान की पार्टी तहसिले इस्लाम के लगभग 24 संसद बगावत में उत्तर गए और इमरान को नेशनल असेंबली बंद करने की सिफारिश राष्ट्रपति को करनी पड़ी। राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली भंग कर दी है। विपक्षी नेता बिलावल भट्टो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शहबाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पार्टी के उपाध्यक्ष मरियम नवाज, विपक्ष की सशक्त आवाज मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खतखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक या 2 दिन में सुनवाई कर फैसला करने का आदेश दिया है। विपक्षियों ने एक जुट होकर शहबाज शरीफ को अपना अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। इमरान खान से सेना के सदर कमर जावेद बाजावा ने भी उनको दो टूक शब्दों में कह दिया है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। पाकिस्तान में इमरान की गद्दी अब जा चुकी है। इमरान ने विदेशी साजिश का बहाना बनाकर नेशनल असेंबली भंग करवा दी है। क्रिकेट में वर्ल्ड कप जिताने वाले पाकिस्तान के हीरो, पढ़े-लिखे इमरान खान ने अपनी सारी छवि को खराब करते हुए अब जाड़ टोने का सहारा लेना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की जनता इमरान की इस व्यवहार से आश्वर्यचिकित की। पाकिस्तान की

जादू टान का इ. और इमरान

जार इनरान के बाहर हो 5 बच्चों की मुगलाते में थे गदी बचाने में धरी रह गई। श्वास प्रस्ताव असेंबली के सांसद है, और उत्तर थी। इसके 24 से 30 सिंध हाउस में अविश्वास नान के पक्ष में गिराना निश्चित जर डाले तो 5 अब तक भी अपना अपना प्रधानमंत्रीयों के जनरल निकिन सरकार ने तो जनरल गोपनीय लगाकर बने पर दोनों शरीफ अब हैं अब छोड़कर विदेश भाग गए हैं। उनके 3 साल के कार्यकाल में पाकिस्तान में महंगाई का पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, महंगाई 35% ऊंचाई पर पहुंच गई मुद्रास्फीति भी आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वैश्विक समुदाय का भरोसा पाकिस्तान की सरकार से टूट गया है ऐसे में वहां का विपक्षी दल एवं नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और अन्य दल इमरान सरकार पर निशाना साधे हुए हैं इमरान खान और सेना के जनरल बाजवा के बीच भी भारी मनमुटाव की रिति आ गई सेना भी चाहती है कि अब विपक्षी दलों के साथ मिलकर नवाज शरीफ जैसा ट्रिल शूटर प्रधानमंत्री पाकिस्तान में स्थापित किया जाए जिससे पाकिस्तान की तमाम समस्याओं का इलाज खोज लिया जाए। नवाज शरीफ के रूस, चीन, सऊदी अरेबिया और अमेरिका से संबंध इमरान सरकार की तुलना में अच्छे ही रहे हैं इमरान सरकार ने वैसे भी विश्व समुदाय को धोखे में रख हमेशा कदर्यपथियों एवं आतंकवादियों को पनाह दी है अफगानिस्तान ने अमेरिका से अरबों डालर की सहायता लेकर भी तालिबानी आतंकवादियों को लगातार अस्त्र शस्त्र और राजनीतिक मदद अमेरिका को धोखे में रखकर देता आया है पंजशीर घाटी में भी उसने तालिबानियों को सैनिक तथा हवाई हमले की मदद देकर अब अफगानी लड़कों से लोहा लेकर से खाली करवाया है।

कांशी राम की मेहनत पर पानी फेरती मायावती

निर्मल रानी

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पिछले दिनों संपन्न हुए चुनावों में जहाँ भारतीय पार्टी अपनी सीटों में 2017 की तुलना में 57 सीटें कम आने के बावजूद सत्ता में वापस आ गयी वहाँ समाजवादी पार्टी ने बेतहरीन प्रदर्शन करते व अपने मत प्रतिशत में भी इजाफा करते हुये 2017 के मुकाबले लगभग 64 सीटें अधिक हासिल कर कुल 111 सीटों पर विजयी होने के बावजूद सत्ता के जार्डुइ आंकड़े से काफी दूर रही। परन्तु इन चुनावों में सबसे अधिक नुकसान बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ा जिसे 2017 के मुकाबले 18 सीटें और गंवाकर राज्य की मात्र एक सीट पर ही जीत हासिल हुई। और उस एकमात्र विजयी प्रत्याशी उमाशंकर सिंह के विषय में भी यही बताया जा रहा है कि उसने आपने जिसी ज्ञानशम वाहाना का पलता यह जाहाजिल की है न की मायावती के समर्थन अथवा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के नाते। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के अंतर्गत रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विजयी बसपा से निर्वाचित एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह इससे पूर्व भी 2012 व 2017 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र में समाजसेवी के साथ साथ उनकी रोबिन हुड जैसी छवि बनी हुई है। यही उनकी जीत का प्रमुख कारण माना जा रहा है। सबाल यह है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्य मंत्री रहने वाली मायावती के नेतृत्व में ऐसी क्या कमी रह गयी कि जो मायावती अपनी पार्टी के जनाधार की बदौलत देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सपने संजोने लगी थीं आज उनकी वही बसपा मूर्त पाया गया ज्ञानशम क्षेत्र दल क्षम्य बलिया जाना है? ना, यहाँ बहुजन 1984 न कांशीराम ने देश में 85 प्रतिशत बहुजनों के मतों के बल पर 15 प्रतिशत सवर्णों द्वारा देश पर राज करने जैसी 'फिलॉसफी' को सामने रखकर बसपा का जनाधार पूरे देश विशेषकर उत्तर प्रदेश में बढ़ाया था। और 85 बनाम 15 प्रतिशत के इसी फामूले ने उनकी पार्टी को आसमान पर पहुंचा दिया था। कांशीराम जीवन भर अपनी करनी शुरू कर दी। दलित समाज के मतों पर अपना एकाधिकार समझने के बाद मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलनों की तरह न तो कोई मुस्लिम सम्मलेन आयोजित किये न ही वे कभी बलि नहीं चढ़ाई। कांशीराम ने 2001 में सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर कुमारी मायावती को अपना उत्तराधिकारी तो जस्ता बनाया परन्तु 2006 में कांशीराम के देहांत के बाद मायावती ने न केवल बसपा संगठन पर पाया गया ज्ञानशम की बदौलत 'न बलि

नाम सत्ता पर रख न बनाना तरकी सर्क त कई बार पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों से भी समझौता किया। यहाँ तक कि वे कई बार अपने मुख्य नारों को यू टर्न देते हुये अपनी पार्टी की मूल विचारधारा से समझौता करती भी नजर आ। इ

। बहुजन समाज के साथ साथ मायावती ने सर्वजन समाज की बात भी करनी शुरू कर दी। दलित समाज के सिर पर फोड़ा जबकि मायावती ने मुस्लिम मतों के लिये ब्राह्मण सम्मेलनों की तरह न तो कोई मुस्लिम सम्मलेन आयोजित किये न ही वे कभी बलि नहीं चढ़ाई। कांशीराम ने गलियां देते व अपमानित करते फिरती थीं उसी समाज को आर्कित करने के दुःख दर्द की साथी बनती दिखाई दीं। इसके बावजूद उनका गुरुसा राज्य के मुस्लिम मतदाताओं पर फूटना उनकी राजनीतिक अदूरदर्शिता के साथ साथ किसी 'प्रायोजित व नियोजित' साजिश का भी षड्यंत्र बनाया गया ज्ञानशम की बदौलत 'न बलि

हाना' न बिसलाइ-समन्वय इयर के हुए न उठार के हुए' जैसी हो गयी। न ही उहें 85 प्रतिशत समाज वाले पारंपरिक बोट मिले न ही 15 प्रतिशत समाज के बह मत हासिल हुए जो पहले भी कभी नहीं मिला करते थे परन्तु मायावती ने अपनी इस ऐतिहासिक हार का ठीकरा दलियों या ब्राह्मणों पर नहीं बल्कि मुस्लिमानों के बाद मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलनों की तरह न तो कोई मुस्लिम सम्मलेन आयोजित किये न ही वे कभी बलि नहीं चढ़ाई। कांशीराम ने गलियां देते व अपमानित करते फिरती थीं उसी समाज को आर्कित करने के दुःख दर्द की साथी बनती दिखाई दीं। इसके बावजूद उनका गुरुसा राज्य के मुस्लिम मतदाताओं पर फूटना उनकी राजनीतिक अदूरदर्शिता के साथ साथ किसी 'प्रायोजित व नियोजित' साजिश का भी षड्यंत्र बनाया गया ज्ञानशम की बदौलत होता है।

जिस तरह खुली हवा में टहलने से स्वास्थ्य बना रहता है उसी तरह पार्टी बदलते रहने से नेता जी की रौनक बनी रहती है। यही बजह है कि पिछले चार साल में चार सौ से अधिक बड़े नेताओं ने पार्टीयों की ऐसी अदला-बदली की तरफ आया है।

पाटी सिद्धांत से खुद का बड़ा समझना एक सफल नेता की निशानी होती है। नेताजी कपड़े बदलें न बदलें पार्टी जस्ता बदलना चाहिए। ऐसा करने से उनकी नेतागिरी की धाक बनी रहती है। सबकी अपनी-अपनी जस्तरते होती हैं। सबके अपने-अपने पेट और मुँह होते हैं। फिर नेता जी की जस्तरतों का मुँह कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। न ये कभी भरा था, न भरा है और न कभी भरेगा। ओलॉपिक्स में लांग जंप करने वाला खिलाड़ी हार जाए तो खाली हाथ लौटा है जबकि नेता दाँए-बाँए, ऊपर-नीचे हर दिशा में जप करके कुछ न कुछ हथिया ही लेते हैं। वह भी न मिले तो बाज़ वाले का ही सही हड्डपने की काबिलियत तो रखते ही हैं।

जिस तरह खुली हवा में टहलने से स्वास्थ्य बना रहता है उसी तरह पार्टी बदलते रहने से नेता जी की रौनक बनी रहती है। यही बजह है कि पिछले चार साल में चार सौ से अधिक बड़े नेताओं ने पार्टीयों की ऐसी अदला-बदली की तरफ आया है। आज तक उसकी खोज जारी है। हाल ही में विकास नाम का एक प्राणी पुलिस वालों के अलग का रस में नेताजा न चारा-चारा, चुपके-चुपके पार्टी बदल ली। और पाटी भी वही जिसे वे बरसों से गरियाते रहे। गरिया-गरियाकर उनका मुँह गरियाने का शोधालय बन गया। अब ऐसे शोधालय से गरियाने की खरी न निकलेगी तो मीठी-मीठी फुलजड़ी झड़ेंगी? पार्टी बदलने के बाद मीडिया का सामना करना कोई इनसे सीखे। यह पूछने पर कि आपने पार्टी क्यों बदली तो हाजनता, निर्वाचन क्षेत्र और देश के विकास के खातिर जैसा कर्णप्रिय बनलाइनर कहकर सबके मुँह पर ताला लगा देते। जबकि इस बनलाइनर का गुदार्थ रहिमन पानी राखिए वाले पानी से भी भारी था। अब भला कोई नेता जी को कौन बताएं कि विकास नाम का जीव अंगेजों के जमाने से ही गयब है। आजादी के बाद सीधीआई, आईबी, रॉ, ईडी सभी को इसी के पाछे लगा दिया। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। आज तक उसकी खोज जारी है। हाल ही में विकास नाम का एक प्राणी पुलिस वालों के

विदेश संदेश

ब्राजील में बारिश से आठ लोगों की मौत
रियो डी जिनेरियो। ब्राजील के रियो डी जिनेरियो राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने यह जानकारी दी। राज्य में रात से



बारिश शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही। भीषण बारिश के कारण क्षेत्र और आस पास के इलाकों में बाढ़ अगयी।

दमकल कर्मचारियों ने आगा डोस रेड्स शहर में पांच लोगों के मरे जाने की पुष्टि की है, इसके अलावा पास के परापर और मेसक्यटा में तीन और लोगों की मौत हुई। कम से कम आठ लोग अब भी लापता हैं। गोरक्षक है कि कीरब दो माह पहले रियो डी जिनेरियो के उत्तर में पहाड़ी इलाके पेट्रोपलिस में भूस्खलन की घटनाओं में दो सौ से ज्यादा लोग मरे गए थे।

श्रीलंका में विपक्षी सांसदों ने आपातकाल लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया

कोलंबो। श्रीलंका में मुख्य विपक्षी दल समाजी जन बलवंगया (एसजी) के सांसदों ने कार्यसूची आदेशों की अवज्ञा करते हुए यहां प्रदर्शन किया। विपक्षी दल के सांसद, देश में अब तक के सबसे खारब अधिक संकट के बीच आपातकाल और अन्य पार्टियों लगाने के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे कदम का विरोध कर रहे हैं। श्रीलंका की अधिकांश आवादी का व्हाट्सएप, ट्वीटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों से संपर्क टूट गया। सकार ने अपने खिलाफ प्रदर्शनों को आयोजित करने में इनका इस्तेमाल किए जाने का आपातकाल लगाने का निर्धारण लिया है। साइबर और इंटरनेट शासन पर नजर रखने वाले निरागरान संगठन 'इंटरब्लॉक्स' ने श्रीलंका में मध्यवर्ती लगाव को अवधारणा की अपेक्षा की। विपक्षी सांसद हर्ष डी सिल्वा ने कहा, "हम श्रीलंका में लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।" विपक्षी सांसदों ने कोलंबो के इंडियनेस स्कायर की ओर मार्च करते हुए नारे लगाए और तिक्तांग दिखायी, जिन परियाएँ थीं : "दमन बंद करों" और "गोंत्रा जाओं।" पुलिस अधिकारी ने स्कायर तक जाने वाले रास्तों पर अवरोध लगा दिया। यह स्कायर 1948 में श्रीलंका की आजारी की याद में बनाया गया था। 'कोलंबो पेज' अखबार की खबर के अनुसार, श्रीलंका इंपरियल ने कफ़्थू का उल्लंघन करने पर देश के पश्चिमी प्रांत में 664 लोगों को गिरफतार किया। ये गिरफतारियां शनिवार रात 10 बजे से रविवार सुबह छह बजे के बीच जरूरी अभियान के दौरान की गयी। उन्होंने बताया कि कफ़्थू का उल्लंघन कर रहे लोगों को पकड़ने के लिए देशभर में और अविनान चलाए जा रहे हैं।

मैक्सिको में गोलीबारी में कम से कम तीन लोगों की मौत

मैक्सिको सिटी। मैक्सिको के अकापुल्को में समुद्र तट के पास स्थित एक रेस्टरां में गोलीबारी और बाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई।

ओडेसा। रूस-यूक्रेन के बीच 39वें दिन भी जंग जारी है। जंग के 40 वें दिन रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर जबरदस्त यात्राकारी पर्यावरण की ओर आक्रमण की। इस हवाई हमले में यूक्रेन के ओडेसा को भारी नुकसान हुआ है। ओडेसा क्षेत्र सैन्य प्रशासन के आपरेशनल स्टाफ के प्रवक्ता सेर्ही ब्रैकुक ने कहा ओडेसा पर कई मिसाइलें लांच की गई। जिसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक, वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और संबंधित सेवाएं काम कर रही हैं।

ओडेसा सिटी कार्डिनल ने दी जानकारी

एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया कि ओडेसा में सूर्योदय से पहले इंधन डिपो में

एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया कि ओडेसा के भारी नुकसान हुआ है।

बाद में, पुलिस ने हमलावारों का पीछा किया और मुठभेड़ में एक हमलावर को ढेर कर दिया, जबकि दूसरा पैरीरूप से जखमी हो गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो में दिख रहा है कि लोग गोलीयां चलने के बीच समुद्र तट पर इधर-उधर भाग रहे हैं, जबकि कुछ लोग में या कुसियों की आड़ लेकर छिप गए।

रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर दागी कई मिसाइल, शहर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पहुंचा दिया

एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया कि ओडेसा में सूर्योदय से पहले इंधन डिपो में

एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया कि ओडेसा के भारी नुकसान हुआ है।

60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े

किंतु गोलीबारी और खदानों के खरारे के कारण 60 से अधिक विदेशी जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

यूक्रेनी बंदरगाहों पर हैं खड़े